



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252051
CG-DL-E-13022024-252051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945

No. 632]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

का.आ. 663(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या तलाशी वारंट की तामील या निष्पादन करने के लिए समझौता किया गया है:

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (पप) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन, या

(ख) किसी व्यक्ति को उसे हाजिर होने और दस्तावेजों या अन्य चीज को प्रस्तुत करने या उसे हाजिर करने के लिए समन, या

(ग) तलाशी वारंट

भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् न्याय मंत्री अथवा महाभियोजक या रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, जिसे वह प्राधिकृत करें, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले उस देश के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को जारी किया जा सकेगा, ताकि उसमें नामित व्यक्ति को अथवा स्थान पर उस समन की तामील अथवा वारंट का निष्पादन किया जा सके।

2. भारत में संबंधित न्यायालय, न्यायाधीश, या मजिस्ट्रेट से समन जारी करते समय गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/52/2019-विधिक प्रकोष्ठ, तारीख 04 दिसम्बर, 2019 में अंतर्विष्ट व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

3. ऐसा समन या वारंट रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् न्याय मंत्रालय अथवा महाभियोजक अथवा पोलैंड की सरकार के ऐसे व्यक्ति जिसे वह प्राधिकृत करे, को पारेषित करने के लिए आईएस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 663(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Poland for service or execution of summons or search warrant in relation to criminal matters, on any person in Republic of Poland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that –

- (a) a summons to an accused person; or
- (b) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it; or
- (c) a search-warrant,

may be issued by a Court in India in duplicate to the Court, Judge or Magistrate in the Government of the Republic of Poland having authority under the law for the time being in force in that country, through the Competent Authority, that is, the Minister of Justice or the Prosecutor General or a person who he or she authorises of the Government of Republic of Poland to serve such summons or execute such warrant on the person or place named therein.

2. The concerned Court, Judge or Magistrate in India, while issuing summons are required to comply with the comprehensive guidelines issued by Ministry of Home Affairs, *vide* letter No.25016/52/2019-LC, dated the 4th December, 2019.

3. Such summons or warrant shall be sent to the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Competent Authority, that is, the Minister of Justice or the Prosecutor General or a person who he or she authorises of the Government of Republic of Poland.

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

क्र.आ. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या तलाशी वारंट की तामील या निष्पादन करने के लिए समझौता किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उस मामले में जहां भारत का कोई न्यायालय किसी ऐसे समन या तलाशी वारंट का निष्पादन करता है जो रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से प्राप्त हुआ है, वहां तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें, ऐसे समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को आईएस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अग्रेषित की जाएगी।

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 664(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Poland for services or execution of summons or search- warrant in relation to criminal matters on any person in Republic of Poland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that in case where a Court in India executes any summons or search-warrant received from a Court, Judge or Magistrate in the Government of the Republic of Poland, having authority under the law for the time being in force in that country, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing such summons or search-warrant through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

का.आ. 665(अ). केन्द्रीय सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या निष्पादन करने के लिए समझौता किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी आपराधिक मामले में किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन, जिसे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी स्थान पर तामील या निष्पादन किया जाना है, को इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसे समन को गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/52/2019.विधिक प्रकोष्ठ, तारीख 04 दिसम्बर, 2019 में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार आईएस -2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा, जो उसे सक्षम प्राधिकारी अर्थात् रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के न्याय मंत्री अथवा महाभियोजक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को पारेषित करेगा।

प्ररूप**साक्षियों को समन**

[दंड प्रक्रियासंहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिये]

सेवा में

रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में न्यायालय या न्यायाधीश /मजिस्ट्रेट.....

(द्वारा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार का न्यायमंत्री या महाभियोजक या ऐसा व्यक्ति जिसे वह प्राधिकृत करे)

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि (अभियुक्त का नाम)(पता)(या जो उस बात के लिए संदिग्ध है) ने अपराध(समय और स्थल के साथ अपराध का संक्षिप्त विवरण) कारित किया है और मुझे यह प्रतीत होता है कि आप अभियोजन के लिए तात्त्विक साक्ष्य दे सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत कर सकते हैं;

इसलिए आप ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए या इसका साक्ष्य देने के लिए कि आप उक्त आवेदन के विषय के बारे में क्या जानते हैं, न्यायालय के समक्ष.....दिन को.....प्रातः/अपराहन में हाजिर हों, और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं और आपको इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर नहीं होंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर होने से बाध्य करने के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख20को प्रदत्त किया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 665(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Poland, for services or execution of summons in relation to criminal matters on any person in Republic of Poland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a summons for attendance of a person in the course of an investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the Republic of Poland, shall be issued in the Form annexed hereto, and such summons shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Competent Authority, that is, the Minister of Justice or the Prosecutor General or a person who he or she authorises of the Government of the Republic of Poland as per the guidelines issued by Ministry of Home Affairs, vide letter No.25016/52/2019-LC dated the 4th December, 2019.

FORM

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court or Judge/Magistrate in the Republic of Poland.....

(Through the Competent Authority, that is, the Minister of Justice or the Prosecutor General or a person who he or she authorises of the Government of the Poland)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on theday of.....atA.M./P.M. to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court thisday of20

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate.

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

का.आ. 666(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में दांडिक मामलों के संबंध में रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में निवास करने वाले साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए समझौता किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विहित करती है कि --

- (क) पोलैंड गणराज्य में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररूप में, पोलैंड गणराज्य के किसी सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा; और
- (ख) ऐसा कमीशन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आईएस-2 प्रभाग को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् न्याय मंत्री या महा अभियोजक या किसी व्यक्ति, जिसे पोलैंड गणराज्य की सरकार प्राधिकृत करती है, को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

प्ररूप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

[दंड प्रक्रियासंहिता, 1973 की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए]

.....

..... के न्यायालय में

सेवा में

.....

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से)

यह प्रतीत होता है कि..... के न्यायालय में..... बनाममामला संख्या.....में न्याय के उद्देश्य सेका साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा/रही है, और उसकी उपस्थिति को अयुक्तियुक्त विलंब, व्यय या असुविधा के बगैर उपाप्त नहीं किया जा सकता है, मैं.....इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूँ कि आप उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए, उक्त साक्षी को ऐसे समय और स्थान पर, जो आप नियत करें, हाज़िर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं, जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार, आपके समक्ष अपने काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं हैं तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा कर सकेगा;

और, मैं, आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लेखबद्ध करवाएंगे और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिह्नित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुहर और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को आईएस -2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें।

तारीख.....20..... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 666(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Republic of Poland for taking the evidence of witnesses residing in Republic of Poland in relation to criminal matters in Courts in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby prescribes that -

- (a) commission for examination of witnesses in Republic of Poland shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any competent criminal court of Republic of Poland having authority under the law for the time being in force in the Republic of Poland; and
- (b) such Commission shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Competent Authority, that is, the Minister of Justice or the Prosecutor General or a person who he or she authorises of the Government of the Republic of Poland.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973]

IN THE COURT OF.....

.....

To

.....

(Through the Government of India, Ministry of Home Affairs,

New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of is necessary for the ends of justice in case No....., Vs..... in the Court of and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for *viva voce*);

Any party to the proceeding may appear before you through his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly

marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through IS II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this..... day of.....20.....

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate,

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

का.आ. 667(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने के लिए समझौता किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा।

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 667(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Republic of Poland for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Poland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in the Republic of Poland having authority under the law in force in the Republic of Poland as the Courts by which the Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

का.आ. 668(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ पोलैंड की सरकार के साथ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने के लिए समझौता किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या अर्हता के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 12015/2/2023-आईसी-III]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

S.O. 668(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Republic of Poland for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Poland;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to Republic of Poland with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No.12015/2/2023-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.